जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं, या तो जीतते है या फिर शसिखतेश है । –अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून, मंगलवार, 17 अगस्त 2021

पेज थ्री
www.page3news.in

सामान्य जनजीवन की ओर वापसी

दूसरी लहर ने दिल्ली और मुंबई समेत पूरे देश को जिस तरह के दृश्य दिखलाए हैं, उनसे उबरने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी यह कम बड़ी बात नहीं है कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम महामारी के इस चरण को पार करने की स्थिति में आ सके हैं। सख्त लॉकडाउन से इसमें काफी मदद मिली।

मोहन शर्मा।।

राहत की बात है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से काफी हद तक उबर कर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और वित्तीय राजधानी मुंबई समेत देश के कई हिस्से आज से सामान्य जनजीवन की ओर वापसी की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हालांकि इस दूसरी लहर ने दिल्ली और मुंबई समेत पूरे देश को जिस तरह के दृश्य दिखलाए हैं, उनसे उबरने में लंबा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी यह कम बड़ी बात नहीं है कि सीमित संसाधनों के बावजूद हम महामारी के इस चरण को पार करने की स्थिति में आ सके हैं। सख्त लॉकडाउन से इसमें काफी मदद मिली। हालांकि उसकी जो कीमत एक अर्थव्यवस्था के रूप में हमें चुकानी पड़ी है, वह भी कम नहीं। इसीलिए यह ज्यादा जरूरी है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करते हुए भी पूरी सावधानी बरती जाए। इसी सावधानी के तहत दिल्ली में बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को ऑड–इवेन बेसिस पर ही खोलने की इजाजत दी गई है। मेट्रो भी 50 फीसदी सीट क्षमता के साथ ही चलेगी। महाराष्ट्र में यह सावधानी और स्पष्ट रूप में दिखती है, जहां पूरे राज्य को कोरोना संक्रमण की स्थिति के आधार पर पांच अलग–अलग लेवल में बांटा गया है। लेवल 1 के शहरों में सबसे ज्यादा छूट दी गई है और लेवल 5 के शहरों में सबसे कम।

मुंबई फिलहाल लेवल 3 में है, इसलिए वहां लोकल यात्रा पर रोक समेत बहुत सारी पाबंदियां जारी रहेंगी, पर फिर भी कुछ शर्तों के साथ बाजार, मॉल और सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। यह न केवल अर्से से घरों में बंद लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक राहत साबित होगा बल्कि बंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों के चलते आर्थिक तंगी से गुजर रहे परिवारों के लिए भी नई उम्मीद लाएगा। मगर इसी बिंदु पर यह याद करने की जरूरत है कि महामारी की पिछली लहर उतरने के बाद अनलॉक शुरू होने पर हमने जिस तरह की लापरवाही दिखाई थी, वह कितनी भारी पड़ी। आज जो तीसरी लहर का खतरा विशेषज्ञ बता रहे हैं, वह तो अपनी जगह है ही, उससे बड़ी सचाई यह है कि दूसरी लहर भी पूरी तरह थमी नहीं है। देश के कई हिस्सों में यह अभी भी गंभीर रूप में है और उस पर काबू पाने के प्रयास चल ही रहे हैं।

जाहिर है, आगे की राह बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगी कि दूसरी लहर के उतार के बाद मिले इस वक्त का हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस लिहाज से दो सवाल अहम हैं। पहला, कितनी बड़ी आबादी टीकों के सुरक्षा घेरे में कितनी जल्दी लाई जा सकती है और दूसरा, अनलॉकिंग के दौरान सामान्य जीवन जीते हुए हम कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कितनी सजगता बनाए रख पाते हैं। पहला सवाल खासतौर पर सरकारी तंत्र और हेल्थकेयर ढांचे से वास्ता रखता है तो दूसरा सामान्य नागरिकों से। दोनों के सम्मिलित प्रयासों से ही वायरस के खिलाफ यह कठिन जंग निर्णायक रूप से जीती जा सकती है।

धर्म–कर्म

अशोक वोहरा।
प्रमुख स्मृति ग्रन्थ हैं– मनु स्मृति, रामायण, महाभारत और 18 पुराण। श्रीमद्भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। वेद ही धर्मग्रंथ है दूसरा अन्य कोई नहीं। अब यदि आप हिन्दू हैं तो आपको धर्म–कर्म के कौन से कार्य करना चाहिये यह भी जानना जरूरी है। वैसे समाज में तो सैंकड़ों और हजारों तरह के रीति रिवाज प्रचलित है लेकिन सभी का धर्म से संबंध नहीं होता। रिवाज की उत्पत्ति स्थानीय लोक कथाओं, संस्कृति, अंधविश्वास, रहन–सहन, खान–पान आदि के आधार पर होती है। दरअसल लोगों की जिंदगी से संबंध रखने वाला काम रिवाज होता है। यह रिवाज एक जगह या वहां के लोगों के लिए आम होता है। हालांकि बहुत से ऐसे रिजाव है जो पौराणिक कथाओं के आधार पर भी समाज में प्रचलित हो जाते हैं, लेकिन वह कितने उचित है इस पर बहस हो सकती है।

संपादकीय

अमेरिका है अलग

अमेरिकी विश्वविद्यालयों का हाल देखिए। वहां सीनियर प्रफेसरों को बजट दे दिया जाता है। वे जरूरत के मुताबिक जब चाहें पैसे देकर नई दिल्ली, तोक्यो या इस्तांबुल से किसी को भी पढ़ाने–लिखाने के लिए बुला सकते हैं। वहां पहले से मंजूरी लेने के बजाय समय–समय पर समीक्षा करने का सिस्टम है। इसमें यह देखा जाता है कि कोई अपने अधिकार का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा। मुझे पता है, ऐसा सिस्टम अपनाने से शुरू में कुछ करप्शन और दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन अभी जो हाल है, उसे देखते हुए बदलाव की कोशिश करनी चाहिए। फिर बात यह भी है कि कुछ मामलों में एक तरह की फाइनल अथॉरिटी होने से भरोसा पैदा होता है, जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है और ईमानदारी भी। एक तरफ तो यह बात काफी अच्छी लगती है कि सभी सीनियर सिविल सर्वेंट्स कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि वे अमूमन किसी मंत्री या सांसद के लिए बैक–एंड पर हर वक्त हुक्म बजा रहे होते हैं। ऊंचे सपने, काम के प्रति लगन या शोषण, चाहे जो वजह हो, ये सीनियर ब्यूरोक्रेट इस हद तक काम कर रहे होते हैं कि कुशलता, कल्पना और क्रिएटिविटी पर आंच आने लगती है। ये लोग शुरू में बहुत तेजतर्रार होते हैं, लेकिन बाद में तोते जैसे हो जाते हैं। ऐसे में सरकारी कामकाज में रचनात्मकता की उम्मीद कैसे की जा सकती है। शुरुआत में कुछ दुरुपयोग हो सकता है इस सिस्टम का, लेकिन यह भी तो देखें कि हर तरह के चेक एंड बैलेंस के बावजूद करप्शन खत्म तो नहीं हुआ है।

कहा जाता है कि लोकतंत्र में तो ऐसा होता ही है। कोई भी फैसला बहुमत की राय से होना चाहिए। इसे 'वर्टिकल डेमोक्रेसी' कहें तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक और रूप भी हो सकता है।

फाइलों का चक्कर

कौशिक बसु।।

इकॉनमिक पॉलिसी क्यों निहायत खराब बन जाती है, इसकी बहुत साफ वजह है। नेताओं की आम सहमति से नीतियां बनाई जाएंगी, तो उनके लचर होने का जोखिम बना रहेगा। इस तरीके से अगर हवाई जहाज बनाया जाए तो उसके डैने ऊपर की ओर उठे होंगे क्योंकि अधिकतर लोगों की नजर में वही ठीक होगा। उसकी नोज बाईं ओर मुड़ी होगी क्योंकि ज्यादातर लोग वही चाहते होंगे। ऐसे में तो वह विमान उड़ने से रहा।

दरअसल भारतीय लोकतंत्र में एक दिक्कत है। हर फैसले में सभी लोग शामिल हो जाते हैं। कोई भी चीज मंजूर होने से पहले एक से दूसरे डेस्क पर सरकारी फाइलें घुमाई जाती हैं, नो ऑब्जेक्शन के सिग्नेचर के लिए। कहा जाता है कि लोकतंत्र में तो ऐसा होता ही है। कोई भी फैसला बहुमत की राय से होना चाहिए। इसे 'वर्टिकल डेमोक्रेसी' कहें तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक और रूप भी हो सकता है। इसमें सबकी राय तो होगी, लेकिन हर फैसले के बारे में नहीं। सभी निर्णयों को अलग–अलग कर दिया जाएगा। आप खुद से जुड़े हिस्से के बारे में ही राय दे सकेंगे। भारत को वर्टिकल के बजाय इसी तरह के लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए। परमिशन लेने के वर्टिकल स्ट्रक्चर के कारण फैसले करने में देर होती है।

दरअसल सरकार में शामिल होकर अंदर से इसका कामकाज देखना दिलचस्प अनुभव रहा मेरे लिए। किसी भी अच्छी नीति के बीच राह में फंस जाने की बहुत साफ वजहें दिखती हैं। फैसले करने वाले नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स में एक तो कल्पनाशीलता नहीं दिखती और दूसरे वे बासी आइडिया की गलियों में चक्कर काटते रहते हैं।

भारत की अनाज खरीद नीति को ही ले लीजिए। कई दिक्कतें हैं इसमें। खाने–पीने की चीजों के दाम बढ़ने के मसले पर कई बैठकों में मैं शामिल रहा। उनमें नौकरशाहों का जोर इस बात पर रहता था कि भारत सरकार को हर वक्त खाद्यान्न का एक तय भंडार बनाए रखना चाहिए। वे यह बात नहीं समझ पाते थे कि अगर एक तय मात्रा हमेशा रखी जाएगी तो हो सकता है कि वह भंडार की हैसियत खो बैठे।

कई ऐसे आइडिया होते हैं, जिनसे समस्याओं का जल्द निपटारा हो सकता है या कुछ फौरी राहत मिल सकती है, लेकिन लोगों को बनी–बनाई लीक छोड़ने के लिए राजी करना किसी जंग से कम नहीं होता। मुझे अफसोस है कि अपने आइडिया पर अमल के लिए मैं ज्यादा जोर नहीं लगा सका। मुझे लगता रहा कि इनमें से कुछ तो इतने अच्छे आइडिया हैं कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति सुनते ही इन पर अमल करना चाहेगा। तमाम बैठकों में मैंने जो बातें कहीं, उनमें से कुछ आइडिया पर उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही नजर जाती दिखी।

दूसरे नेताओं के साथ प्रधानमंत्री को जब भी देखा, यही लगा कि वह इन सबसे अलग और बेहतर हैं। नेहरू की तरह भारत के लिए उनमें एक जुनून है। उनसे मेरी बातचीत में कभी भी राजनीति और रोजमर्रा की सियासी उठापटक का जिक्र नहीं हुआ। हमेशा यही बात हुई कि भारत को कैसे और अच्छा बनाया जा सकता है। मुझे पता है कि इसकी कोई खास वैल्यू शायद नहीं है। वोटर ही अगर यह बात समझ सकें तो देश कुछ और बेहतर हो सकता है।

सरकारी कामकाज में दिक्कतें पैदा होने की दो बड़ी वजहें हैं। टॉप ब्यूरोक्रेट्स पर काम का बहुत बोझ और हर बात के लिए मंजूरी लेने का चक्कर।

सूडोकू बवाल-5319

★★★★☆ मध्यम

4			9		6	1		8
6	8							
	1	7	3	8		4		
3	4		6		7			9
5		1	8			2		7
2			5		1		8	4
		3		7	5	8	6	
							9	5
7		6	2		8			1

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
- पहेली का केवल एक ही हल है।

सूडोकू बवाल -5318 का हल

2	9	8	3	5	6	1	7	4
4	5	3	2	1	7	9	8	6
7	1	6	4	8	9	2	5	3
8	2	5	6	9	1	3	4	7
3	6	4	7	2	5	8	1	9
1	7	9	8	3	4	5	6	2
5	4	1	9	7	2	6	3	8
6	3	2	1	4	8	7	9	5
9	8	7	5	6	3	4	2	1

अपना ब्लॉग

जर्मनी की दो-तिहाई आबादी कुशलकर्मी

मोहन। दिक्कत यह है कि युवा शक्ति से परिपूर्ण होने के बावजूद भारत का अधिसंख्य श्रमबल कुशल नहीं है। जहां अमेरिका की लगभग आधी आबादी और जर्मनी की दो–तिहाई आबादी कुशलकर्मी है, वहीं भारत के कुल श्रमबल का 5 फीसदी भी कुशलकर्मी नहीं कहा जा सकता। चीन में कुशलकर्मियों का प्रतिशत अन्य देशों के मुकाबले कम होते हुए भी हमसे बहुत ऊपर 24 फीसदी पर है। वर्तमान भारत की औसत आयु 29 वर्ष है। 86.9 करोड़ के श्रमबल के साथ पूरी दुनिया के श्रमबल का 28 फीसदी हिस्सा आज हमारे पास है। इसी को लक्ष्य कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने की बात कही थी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का गठन कर उन्होंने अपने इस निश्चय पर मुहर भी लगा दी। यही नहीं, देश के एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने के लक्ष्य के साथ उन्हें रोजगार योग्य बनाने के लिए अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई गई है।